विराट कोहली ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड Page-04

tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'तुम्बाड 2' का आगाज़: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री से बढ़ा एक्साइटमेंट Page-05

मिडिल ईस्ट में 'कयामत की रात'

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

मिडिल ईस्ट में पिछले 39 दिनों से जारी तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी ने वैश्विक चिंता को और गहरा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस संघर्ष को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी दबाव में झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है।सीजफायर के लिए तय समयसीमा खत्म होने से पहले ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता और समझौते को नहीं मानता, तो उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि "आज रात इतिहास का एक ऐसा पल हो सकता है, जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा।"ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तय समय तक ईरान ने डील स्वीकार नहीं की, तो उसके पावर प्लांट, पुल और अहम ढांचे को निशाना

बनाया जाएगा। उनके बयान में यह भी संकेत मिला कि अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ ही घंटों में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं।हालांकि, ईरान ने भी इस चेतावनी का करारा जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट कहा कि उनका देश इस संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अंत तक लड़ेगा और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा।अराघची ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका को अब यह समझ आ गया होगा कि ईरान अकेला नहीं है और उसके साथ मजबूत समर्थन खड़ा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर हालात और बिगड़े तो क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है, जिसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं।इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

कांग्रेस का बड़ा दावा, 73 सीटें जीतने का भरोसा

मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खरगे ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 126 सदस्यीय विधानसभा में 72-73 सीटें जीतने में सफल रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार कांग्रेस को पूरा समर्थन मिल रहा है।दूसरी ओर, बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चुनावी रणनीतियों, रैलियों और प्रचार अभियानों के जरिए दोनों पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला होने वाला है। जनता का रुख ही तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी।

3 दिन में बिजली कनेक्शन' का वादा

देरी पर अफसरों की जेब से कटेगा जुर्माना

बिहार सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बिजली सेवाओं में बड़ा सुधार लागू किया है। अब राज्य में नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि महज तीन दिनों के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही थी कि बिजली कनेक्शन के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और प्रक्रिया बेहद धीमी रहती हैइस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। जेडीयू के आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार, यदि तीन दिन के भीतर कनेक्शन नहीं दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। खास बात यह है कि यह जुर्माना सीधे अधिकारी की जेब से वसूला जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेनियम के मुताबिक, हर दिन की देरी पर अधिकारी को 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह कदम सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगने की उम्मीद है, क्योंकि अब देरी करने पर सीधे आर्थिक नुकसान होगा।विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल बिजली विभाग की कार्यप्रणाली सुधरेगी, बल्कि आम जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो अन्य सरकारी सेवाओं में भी इसी तरह की जवाबदेही लागू की जा सकती है। यह फैसला "गुड गवर्नेंस" की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

असम में सियासी टकराव तेज

हिमंत सरमा की चेतावनी से बढ़ी राजनीतिक गर्मी

हिमंत बिस्वा सरमा और पवन खेड़ा के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर राजनीतिक टकराव में बदल गया है। मुख्यमंत्री सरमा ने अपनी पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को कड़ी चेतावनी दी है। सरमा ने कहा कि अगर पवन खेड़ा कहीं भी छिपने की कोशिश करेंगे, तो असम पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और इसके पीछे कांग्रेस नेतृत्व का हाथ है। सरमा ने यह भी कहा कि उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।मामला तब और गंभीर हो गया जब असम पुलिस की टीम पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई। इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है, जबकि बीजेपी इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई बता रही है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद आगामी चुनावों को देखते हुए और भी तीखा हो सकता है। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है, जिससे राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ता जा रहा हैइस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति में भी बहस को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप से चुनावी माहौल और अधिक ध्रुवीकृत हो सकता है, जिसका सीधा असर मतदाताओं की सोच और चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला- मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को लेकर रहा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षामित्रों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उनका मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। बताया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई माह में मिलने वाले भुगतान में यह वृद्धि शामिल कर दी जाएगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी कदम है।उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, कबीर और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का भी निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल से की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका को भी मजबूती देगा। लंबे समय से कम मानदेय के कारण शिक्षामित्रों में असंतोष था, जिसे दूर करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।इसके अलावा, सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। इस फैसले को आगामी समय में शिक्षण व्यवस्था में स्थायित्व और प्रेरणा बढ़ाने वाला कदम भी माना जा रहा है।

1971 की याद दिलाकर दी सख्त चेतावनी
राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है।पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर राजनाथ सिंह ने सख्त प्रतिक्रिया दी।उन्होंने 1971 युद्ध का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को अतीत के परिणाम याद दिलाए।सिंह ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और हर चुनौती का जवाब देगा।यह बयान भारत की आक्रामक और निर्णायक सुरक्षा नीति की ओर इशारा करता है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच तीखी टिप्पणियों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की धमकी पर कड़ा जवाब देते हुए 1971 युद्ध की याद दिलाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चुनौती को हल्के में नहीं लेगा और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान कोलकाता तक जवाब देगा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा कि पाकिस्तान को ऐसे उकसावे वाले बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाया गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। उनका यह बयान पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान आया, जहां उन्होंने सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को इतिहास याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 55 साल पहले पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जब उसका विभाजन हुआ और बांग्लादेश का गठन हुआ। सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से बंगाल की ओर नजर उठाई, तो इस बार परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि भारत किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है और उसकी नीति अब अधिक आक्रामक और निर्णायक हो गई है। रक्षा मंत्री ने अपने हालिया भाषणों में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जो पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है और भारत सतर्क है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए कहा कि भारत का पड़ोसी देश किसी भी समय गलत कदम उठा सकता है। ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। यह बयान भारत की बदलती सुरक्षा नीति और मजबूत सैन्य रुख को दर्शाता है।

वंदे भारत ट्रेन के खाने में मिला कीड़ा, IRCTC ने लिया एक्शन

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

अहमदाबाद से मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन में खाने की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है। यात्रियों को परोसे गए खाने में कीड़ा मिलने की घटना ने न केवल यात्रिओं को चौंका दिया, बल्कि रेलवे की फूड सर्विस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में IRCTC ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का नोटिस भी जारी किया है। यह घटना उस समय सामने आई जब ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने अपने भोजन में कीड़े देखने की शिकायत की। यात्रियों ने इस पूरी घटना की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर कीं, जिससे मामला तेजी से वायरल हो गया। आदित्य डिडवानिया नामक एक यूजर ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और बताया कि उनके खाने में कीड़े पाए गए। हैरानी की बात यह रही कि यह कोई एक मामला नहीं था। उसी कोच में कम से कम दो यात्रियों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। लगातार शिकायतों के बाद कई यात्रियों ने एहतियात के तौर पर भोजन करना ही बंद कर दिया। इससे ट्रेन में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए IRCTC ने तुरंत जांच शुरू की। यह भोजन M/S ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स (RK ग्रुप) द्वारा सप्लाई किया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। IRCTC अधिकारियों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद प्रभावित कोच में डीप क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और ऐसी लापरवाही को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिष्णुपुर में बम हमले में दो बच्चों की मौत, इंटरनेट सेवाएं बंद

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटना सामने आई है। मंगलवार देर रात बिष्णुपुर जिले के मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए बम हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह घटना रात करीब एक बजे की है, जब एक बम सीधे एक आम नागरिक के घर पर आ गिरा। उस समय घर में मौजूद तीनों लोग, एक पांच साल का बच्चा, छह महीने की बच्ची और उनकी मां, अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक हुए धमाके में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां घायल हो गईं। मणिपुर सरकार ने ने इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, थोउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार के निर्देश के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला एहतियातन लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोका जा सके। जिस मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में यह हमला हुआ, वह निचले क्षेत्र में आता है और चुराचांदपुर के पहाड़ी इलाकों के काफी करीब है। यह इलाका पहले भी 2023 और 2024 में जातीय हिंसा के दौरान लगातार गोलीबारी और तनाव का केंद्र रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय भाजपा विधायक टीएच शांति सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद क्रूर और अमानवीय कृत्य बताया। विधायक ने कहा कि यह हमला आतंकवाद से कम नहीं है और समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इतने छोटे और मासूम बच्चों की इस तरह हत्या होना बेहद दुखद और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की

एवरेस्ट रेस्क्यू घोटाले पर सख्ती
सरकार ने बनाई हाई-लेवल कमेटी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

नेपाल सरकार ने एवरेस्ट क्षेत्र में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसका नेतृत्व संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि कुछ ट्रैवल ऑपरेटरों ने झूठी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करके बीमा राशि हड़पने की कोशिश की थी। इसके चलते नियमों को कड़ाई से लागू करने, डिजिटल जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। सरकार ने कहा कि ये घटनाएं पूरे पर्यटन उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, लेकिन रिमोट क्षेत्र में निगरानी में कमी को सुधारने की जरूरत है।तत्काल कदमों में जांच, काले नामों की सूची और दोषियों का सार्वजनिक खुलासा शामिल है।नेपाल पुलिस ने पहले ही 32 लोगों को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीमा घोटाले में आरोपित किया है। कई मामलों में मामूली ऊंचाई की बीमारी वाले यात्रियों को भी हेलीकॉप्टर से निकालकर अलग-अलग बीमा कंपनियों से रकम लेने का प्रयास किया गया। नेपाल सरकार ने यह भी कहा कि लंबी अवधि में तकनीक आधारित रेस्क्यू सिस्टम, गाइड और एजेंसियों के लाइसेंस मजबूत करना, और नैतिक पर्यटन मानकों को लागू करना शामिल है।

इजरायल रक्षा बल की चेतावनी
पूरे ईरान में ट्रेन यात्रा से दूर रहें

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

इजरायल रक्षा बलों ने पूरे ईरान के लोगों से ट्रेनों और रेलवे लाइनों से बचने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। एक्स पर स्थित अपने फारसी भाषा के खाते के माध्यम से जारी की गई इस चेतावनी में नागरिकों से एक निश्चित अवधि के लिए रेल परिवहन का उपयोग न करने का अनुरोध किया गया है। सेना ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस समय से लेकर ईरानी समयानुसार रात 9 बजे (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे) तक, आप पूरे ईरान में ट्रेन का उपयोग और यात्रा न करें। ट्रेनों में और रेलवे लाइनों के पास आपकी उपस्थिति आपके जीवन के लिए खतरा है। इज़रायली सेना द्वारा साझा किए गए एक ग्राफिक में फारसी भाषा में भी यही संदेश था, जिसमें इसे ईरान भर में ट्रेन उपयोगकर्ताओं और यात्रियों के लिए अत्यावश्यक चेतावनी बताया गया था। इस ग्राफिक में ट्रेनों और रेलवे ट्रैक से बचने पर जोर दिया गया था, जो लिखित सलाह के अनुरूप था। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 28 फरवरी को हुए शुरुआती हमलों के बाद से इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष जारी है। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, दोनों पक्ष एक-दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इस चेतावनी में किसी विशेष क्षेत्र या रेलवे मार्ग का उल्लेख नहीं है, जिससे खतरे की सटीक प्रकृति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरानी अधिकारियों की ओर से इस चेतावनी पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, संदेश की भाषा से बढ़ती चिंता का संकेत मिलता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों और देश भर में परिवहन के उपयोग को संबोधित करता है।

संपादक की कलम से

डिजिटल युग में सच की चुनौती: ट्रेंड बनाम सच्चाई

आज का समय "ट्रेंड" का समय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन कोई न कोई मुद्दा अचानक सुर्खियों में आ जाता है और देखते ही देखते लाखों लोगों की राय उसी दिशा में मुड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो ट्रेंड कर रहा है, वही सच भी है?

हाल के दिनों में क्रिकेट से लेकर फिल्मों और शिक्षा तक कई मुद्दे सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अर्शदीप सिंह की पर्सनल लाइफ हो, Tumbbad 2 की शूटिंग या स्कूलों में NCERT किताबों को अनिवार्य करने का फैसला—हर खबर ने सोशल मीडिया पर तेजी से जगह बनाई। लेकिन इन खबरों के साथ कई अटकलें, अधूरी जानकारी और अफवाहें भी उतनी ही तेजी से फैलीं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हर व्यक्ति को "सूचना का स्रोत" बना दिया है। यह लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है—भ्रामक जानकारी (misinformation)। बिना पुष्टि के किसी भी खबर को साझा करना न सिर्फ समाज में भ्रम फैलाता है, बल्कि कई बार किसी व्यक्ति की छवि और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है।

समस्या सिर्फ गलत खबरों की नहीं है, बल्कि "अधूरी सच्चाई" की भी है। जब किसी घटना का एक छोटा हिस्सा वायरल होता है और बाकी संदर्भ छिप जाता है, तो लोगों की राय भी अधूरी जानकारी पर आधारित बनती है। यही कारण है कि आज हमें सिर्फ "फास्ट न्यूज" नहीं, बल्कि "फैक्ट न्यूज" की जरूरत है।

इस स्थिति में जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की नहीं, बल्कि हर डिजिटल यूजर की भी है। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना, विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना और भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न देना—ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

ई-न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है। क्लिक और व्यूज की दौड़ में अगर सच्चाई पीछे छूट जाती है, तो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि मीडिया संस्थान "ट्रेंड" के पीछे नहीं, बल्कि "सत्य" के साथ खड़े हों।

अंततः, ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई स्थायी होती है। एक जागरूक समाज वही है, जो हर वायरल खबर पर सवाल पूछता है और सच की तलाश करता है।

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी
90 लाख से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत करीब 90.83 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।न्यायिक जांच के बाद 27 लाख से अधिक मामलों को 'हटाने योग्य' पाया गया, जबकि कुछ मामलों में प्रक्रिया अभी बाकी है।हटाए गए मतदाताओं को 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपील करने का अवसर दिया गया है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नामों को हटाने की विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया न्यायिक अधिनिर्णय के बाद सोमवार की मध्यरात्रि को संपन्न हो गई है। चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार, राज्य में कुल हटाए गए मतदाताओं की संख्या लगभग 91 लाख तक पहुंच गई है। हालांकि, अंतिम आंकड़े आने के बाद इसमें मामूली वृद्धि हो सकती है, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों द्वारा ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया अभी भी कुल मामलों के एक छोटे से हिस्से के लिए पूरी की जानी बाकी है मुख्य चुनाव अधिकारी, पश्चिम बंगाल के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, न्यायिक अधिनिर्णय के लिए संदर्भित कुल 60,06,675 मामलों में से 59,84,512 मामलों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उन पर न्यायिक अधिकारियों के ई-हस्ताक्षर लगा दिए गए हैं। इन 59,84,512 मामलों में से, न्यायिक अधिकारियों द्वारा 'हटाने योग्य' माने गए और इसलिए हटाए गए मतदाताओं की संख्या 27,16,393 है। इसका अर्थ है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या 90,83,345 है। पिछले साल नवंबर में पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर की अधिसूचना जारी होने से पहले, राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 7,66,37,529 थी। पिछले साल दिसंबर में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 58,20,899 नाम हटाए गए थे। 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में, यह आंकड़ा बढ़कर 63,66,952 हो गया था। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया 'अब, न्यायिक अधिकारियों द्वारा 27,16,393 मामलों को हटाए जाने योग्य पाए जाने के बाद पूरे एसआईआर अभ्यास में पश्चिम बंगाल में हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 90,83,345 हो गई है।' न्यायिक अधिकारियों के ई-हस्ताक्षर लगाने की प्रक्रिया अभी भी 22,163 मामलों के लिए पूरी होनी बाकी है। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद वर्तमान हटाए गए आंकड़ों में कुछ और नाम जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, जिन मतदाताओं के नाम न्यायिक अधिनिर्णय प्रक्रिया में "हटाए जाने योग्य" पाए गए हैं, उन्हें इसके लिए स्थापित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से किसी एक में अपील करने का अवसर मिलेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, न्यायिक अधिनिर्णय अभ्यास के दौरान हटाए जाने योग्य पाए जाने वाले मामलों की अधिकतम संख्या अल्पसंख्यक-बहुल मुर्शिदाबाद जिले से थी। मुर्शिदाबाद से हटाए गए नामों की कुल संख्या 4,55,137 है। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले से 3,25,666 और एक अन्य अल्पसंख्यक-बहुल जिला मालदा से 2,39,375 नाम हटाए गए हैं।

पवन खेड़ा के घर पहुंची पुलिस: सीएम हिमंता की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट के लगाए थे आरोप

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम उनके दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित उनके आवास पर पहुंची है। पवन खेड़ा के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित डी-12 आवास पर असम पुलिस की 4 लोगों की टीम पहुंची है। उनके साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी है। जानकारी के मुताबिक असम पुलिस ने निजामुद्दीन थाने से संपर्क किया था। निजामुद्दीन थाने के पुलिसकर्मी पवन खेड़ा का एड्रेस दिखाने के लिए असम पुलिस को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक पवन खेड़ा अपने घर में नहीं हैं। वे दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्टेट की यात्रा पर हैं। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और कहा था कि जो विदेशी पासपोर्ट दिखाये जा रहे हैं, वे सब नकली हैं। सीएम हिमंता ने यह भी कहा कि इस आरोप के पीछे पाकिस्तानी लिंक है। दरअसल, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर विदेशी पासपोर्ट और बिजनेस को लेकर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी के पास तीन देशों के एक्टिव पासपोर्ट हैं। उनका विदेशों में इन्वेस्टमेंट है और कई संपत्तियां हैं।

पवन खेड़ा के इन आरोपों के बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने कहा कि सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा झूठ कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉप का इस्तेमाल करके किया गया है। बता दें कि हिमंत विश्व शर्मा ने आरोप लगाया था कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए उग्रवादी समूहों से संपर्क करने की कोशिश करने के आरोप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ तीन से चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पवन खेड़ा ने कहा था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर मुख्यमंत्री को उनके कथित भ्रष्टाचार के कारण जेल में डाल दिया जाएगा। हिमंत विश्व शर्मा ने पत्रकारों को बताया, "असम में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए कुछ उग्रवादी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश करने के आरोप में पवन खेड़ा के खिलाफ पहले से ही तीन .चार मामले दर्ज हैं।" उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

असम में अमित शाह का हुंकार:राहुल गांधी पर तीखा हमला

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

गृह मंत्री अमित शाह ने असम के श्रीभूमि जिले के पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनाने की अपील की। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा, साफ सुन लीजिए, हम असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने असम की बराक घाटी की उपेक्षा की, उसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। गृह मंत्री ने दावा किया कि भाजपा ने घुसपैठियों की पहचान कर ली है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनाइए, हमने घुसपैठियों की पहचान कर ली है। अब समय आ गया है कि उन्हें एक-एक कर बाहर किया जाए। शाह ने यह भी कहा कि अगर असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भाजपा-एनडीए की सरकारें बनती हैं तो घुसपैठ पूरी तरह रोकी जा सकेगी। सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करते हुए शाह ने कहा कि केवल भाजपा में करिमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि करने का संकल्प है। उन्होंने

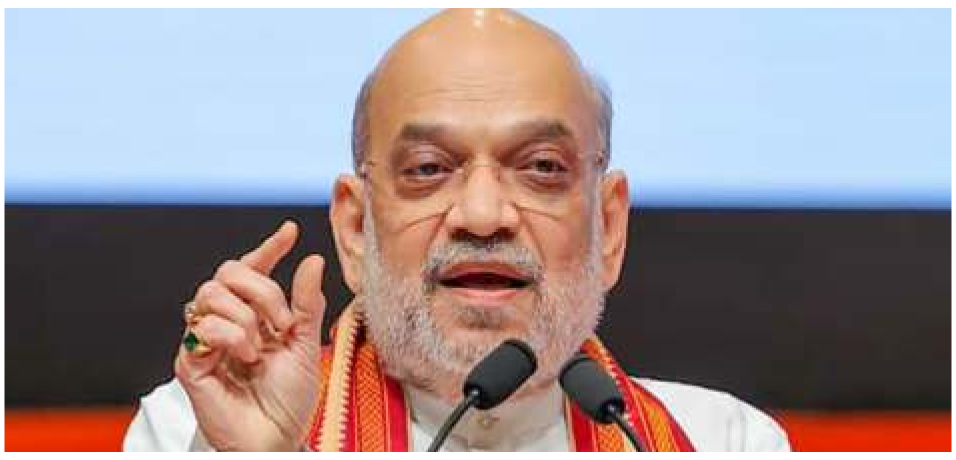

कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सत्ता हासिल करने के लिए घुसपैठियों पर निर्भर रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा असम में जाति, माटी और बेटी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने असमिया और बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का बचाव करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए इसका विरोध करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा कि गुजरात को अनपढ़ों का राज्य बताना अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि यही भूमि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और विक्रम साराभाई जैसी महान हस्तियों की जन्मभूमि रही है। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

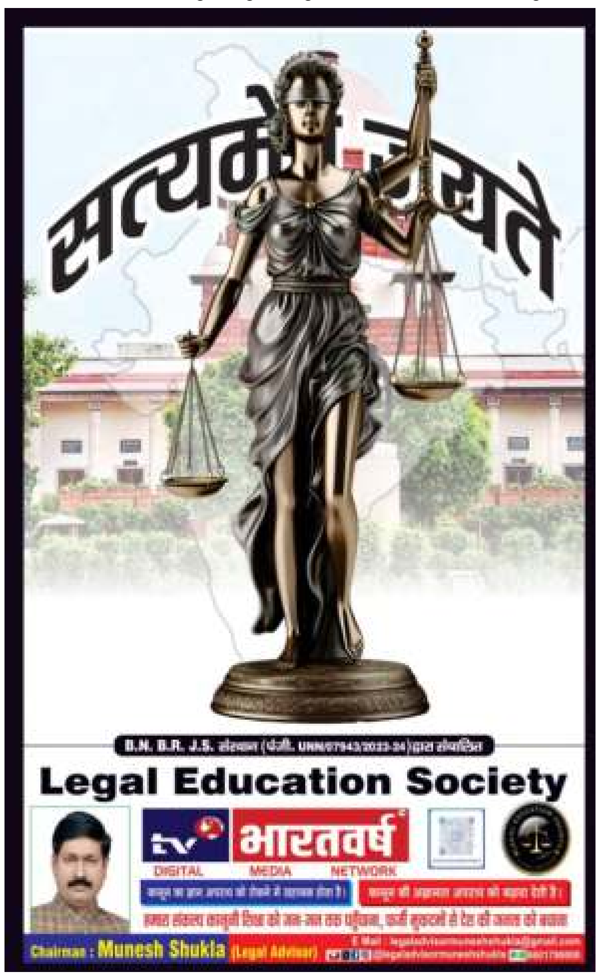

शिक्षाविदों ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई

न्यायपालिका पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद

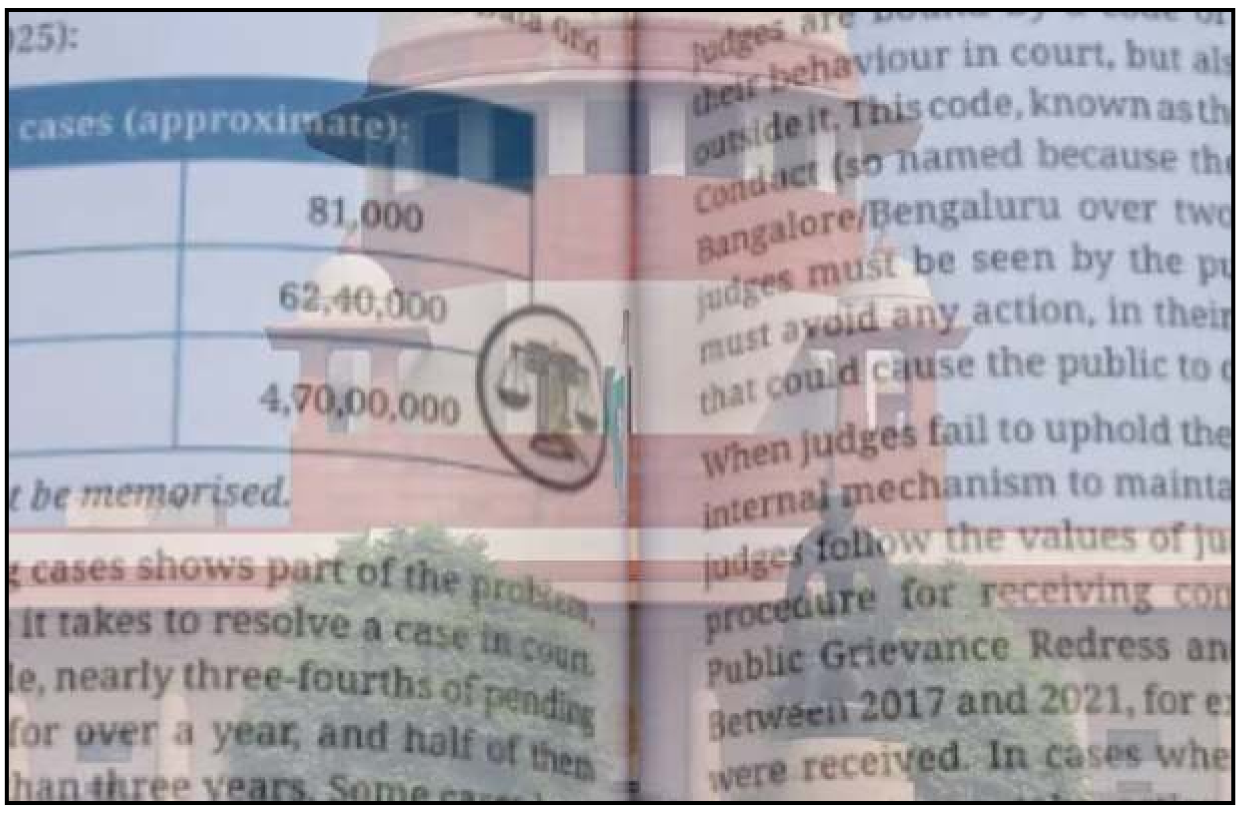

एनसीईआरटी की एक किताब के उस अध्याय को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र था। इस विवाद के कारण तीन विशेषज्ञ शिक्षाविदों को किताब बनाने में अपनी मदद देने से रोक दिया गया था। सोमवार को उन्होंने अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि किताब का मसौदा बनाने का काम किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि यह एक टीम ने मिलकर तैयार किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ को बताया गया कि तीनों विशेषज्ञ - प्रोफेसर मिशेल डैनियन और उनके सहयोगी सुप्रना दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार - कोई "अस्थायी व्यक्ति" नहीं हैं और उनकी "काफी विश्वसनीयता" है। आलोक प्रसन्ना कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अदालत की पिछली टिप्पणियों से उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए आवेदन दायर किए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने शंकरनारायणन से पूछा, "क्या आप अपने कार्यों का बचाव कर रहे हैं?" वरिष्ठ वकील ने कहा कि शिक्षाविद अपने विचार और जानकारी पेश करना चाहते हैं। उनका मकसद यह दिखाना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई कैसे बदल रही है। इसमें कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं।उन्होंने बताया कि कक्षा 6 और 7 की किताबों में भी यह बताया गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और चुनाव आयोग किन मुद्दों का सामना करते हैं। शंकरनारायणन ने यह बात कही और न्यायालय से सुनवाई के लिए समय मांगा, "यह तर्क दिया गया कि न्यायपालिका को अलग-थलग किया गया है। उन मुद्दों पर भी चर्चा हो चुकी है। हम न्यायालय को पूरी प्रक्रिया दिखाना चाहते हैं। ये लोग कोई क्षणिक व्यक्ति नहीं हैं। ये उच्च कोटि के विश्वसनीय शिक्षाविद हैं। लेखक (आलोक प्रसन्ना) स्वयं एक वकील रह चुके हैं और इस न्यायालय के समक्ष पेश हो चुके हैं।" मिशेल डैनियन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि उनके मुवक्किल ने भी स्पष्टीकरण दाखिल किया है। सुप्रना दिवाकर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक ने कहा, "आवेदन का सार यह है कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया थी और किसी भी व्यक्ति को एकमात्र अधिकार या निर्णय लेने का अधिकार नहीं था।" 26 फरवरी को, सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब पर पूरी तरह रोक लगा दी। इसका मतलब है कि इसे आगे छापना, दोबारा प्रकाशित करना या ऑनलाइन साझा करना नहीं होगा। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ ऐसी सामग्री थी, जिसे अदालत ने "आपत्तिजनक" बताया। अदालत ने कहा कि इससे न्यायपालिका पर बहुत गंभीर असर पड़ा है।

यूपी में बड़ा शिक्षा सुधार: 9वीं-12वीं में अब सिर्फ NCERT किताबें अनिवार्य, महंगी प्राइवेट बुक्स पर रोक

उत्तर प्रदेश में छात्रों और अभिभावकों को राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक अहम निर्णय लिया है. इस फैसले के तहत अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों में केवल NCERT और सरकारी मान्यता प्राप्त किताबें ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी. इस कदम को शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और कमीशनखोरी पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है. नए निर्देशों के अनुसार, प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को अब केवल NCERT और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाई करानी होगी. लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि कई स्कूल छात्रों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाते थे.इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था और शिक्षा का खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ जाता था. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब सभी छात्रों को एक समान पाठ्य सामग्री मिलेगी, जिससे पढ़ाई में भी एकरूपता आएगी. इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण स्कूलों में चल रही कमीशनखोरी की प्रथा को खत्म करना है. कई मामलों में यह देखा गया कि कुछ स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ मिलकर किताबें बेचते थे और इसके बदले कमीशन लेते थे.अब जब केवल सरकारी और अधिकृत किताबें ही मान्य होंगी, तो इस तरह की गतिविधियों पर स्वतः रोक लग जाएगी. इससे शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और छात्रों के हितों की रक्षा होगी. इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ छात्रों और उनके अभिभावकों को मिलेगा. पहले जहां एक ही कक्षा की किताबों पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब NCERT की किताबें कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध होंगी.

ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे मैच में बारिश ने डाला खलल

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए महंगा सौदा साबित हो रहे कैमरून ग्रीन

आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा था। कोलकाता की टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह गेंद और बल्ले दोनों से इस सीजन अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन इस सीजन के पहले तीन मैच में कैमरून ग्रीन का प्रदर्शन जैसा रहा है, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ऑक्शन में कैमरून ग्रीन को खरीदकर केकेआर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको बता दें कि कैमरून ग्रीन इस सीजन के शुरुआती मुकाबलों में इंजरी के कारण गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। वहीं, बल्ले से भी उनकी लगातार नाकामी ने केकेआर की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस आईपीएल सीजन में ग्रीन लगातार तीसरे मुकाबले में भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उनकी पारी सिर्फ दो गेंदों तक ही चली। पहली बॉल पर उन्होंने चौका लगाया, तो अगली ही गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। केकेआर ने इस सीजन अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला था। उस मैच में ग्रीन ने 18 रन बनाए। वहीं

हैदराबाद के खिलाफ मैच में ग्रीन 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में वह 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस सीजन वह एक भी मैच में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, तीन मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 24 रन आए हैं। कैमरून ग्रीन आईपीएल में अभी तक 32 मुकाबले खेलने में कामयाब रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 31 पारियों में 36.55 के औसत से 731 रन बनाए हैं। वह आईपीएल में एक शतक दो अर्धशतक ठोक चुके हैं। ग्रीन कितने मुकाबलों के बाद गेंदबाजी करेंगे अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ग्रीन को अब आने वाले मैचों में हर हाल में बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

विराट कोहली ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किया ये कारनामा

आईपीएल 2026 में आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच में जमकर रनों की बारिश हुई। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में 250/3 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में सीएसके दो गेंद बाकी रहते 207 रनों पर ढेर हो गई। आरसीबी ने 43 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 18 गेंदों में 28 रनों की छोटी पारी खेली लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने मुंबई इंडियंस के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल, कोहली सीएसके के खिलाफ 36 मैचों में 1174 रन बटोर चुके हैं। जिसमें 37.87 का औसत रहा। उनका चेन्नई के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर नाबाद 90 है। वहीं, हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित ने कोलकाता नाइट राइडर्स के

सामने 36 मुकाबलों में 1161 रन जुटाए हैं। उनका औसत 40.03 का है। रोहित का केकेआर के खिलाफ सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 109 रन है। रोहित ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में केकेआर के खिलाफ 78 रनों की पारी खेली थी और तब कोहली को पछाड़ा था। हालांकि, कोहली ने 10 दिन के भीतर ही रोहित से आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड छीन लिया। कोहली तीन टीमों के खिलाफ 1100 प्लस रन बनाने वाले एकलौते खिलाड़ी हैं।

अर्शदीप सिंह का 'मिस्ट्री हैंड' वायरल क्या समरीन कौर से डेटिंग की चर्चाएं सच?

IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की, जिसमें वह एक लड़की का हाथ पकड़े हुए थे. अब कुछ फैंस ने हाथ में बने टैटू, नाखूनों पर बने आर्ट से पहचाना और दावा किया कि ये तो समरीन कौर हैं. यहीं से सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि अर्शदीप और समरीन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अर्शदीप सिंह द्वारा शेयर की गई फोटोज में वह एक लड़की का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन इसमें चेहरा नहीं था. लड़की के हाथ पर एक छोटा सा टैटू बना था. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने वाले फैंस लड़की को इसी टैटू से पहचान गए और दावा करने लगे कि ये पंजाबी एक्ट्रेस समरीन कौर है. फैंस कहने लगे कि क्रिकेटर की फोटो में जो लड़की के हाथ में टैटू बना हुआ था, वैसा ही टैटू समरीन के हाथ में भी बना हुआ है. इसके बाद तो समरीन की आईपीएल मैचों की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी. हालांकि ये IPL 2026 का नहीं बल्कि पिछले साल का फोटो है. पंजाबी इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस समरीन कौर सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं और कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 की जीत पर बनी फिल्म 83 में भी

काम किया था, वह क्रिकेटर की मंगेतर के रोल में थीं. समरीन कौर का जन्म 2021 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था. वह 26 साल की हैं और अर्शदीप सिंह से एक साल छोटी हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर डेटिंग के दावों को लेकर न तो क्रिकेटर अर्शदीप और न ही एक्ट्रेस समरीन ने कुछ कहा है.

'बेटी हुई है...' के मैसेज से जीता दिल

सड़क पर निकली 'बिटिया रानी' की पालकी

आज के समय में जहां बेटियों को लेकर समाज की सोच तेजी से बदल रही है, वहीं एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया है. इस वीडियो में एक परिवार अपनी नवजात बेटी के जन्म की खुशी को बेहद खास और अलग अंदाज में मनाता नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार को गुलाबी रंग के गुब्बारों से खूबसूरती से सजाया गया है. कार के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा है- बेटी हुई है'. यह कार सड़कों पर चल रही है और आसपास के लोग इसे देखकर हैरान भी हो रहे हैं और खुश भी. दरअसल, यह कोई आम जश्न

नहीं है. यह एक ऐसा संदेश है, जो समाज को यह दिखाता है कि बेटी का जन्म भी उतना ही खास और खुशी का मौका है, जितना बेटे का. लंबे समय तक हमारे समाज में बेटियों के जन्म को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं रही हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे यह सोच बदल रही है.

वायरल होने की होड़ में सुरक्षा को ताक पर रख रही युवा पीढ़ी

सिर पर रख लिया जलता हुआ चूल्हा

आज के समय में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ ने लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर कर दिया है. कोई अजीबो-गरीब चीजें बनाकर दिखा रहा है, जैसे अंडे की आइसक्रीम, तो कोई खतरनाक स्टंट करके लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है- जैसे सिर या पैर पर चूल्हा रखकर खाना बनाना. हर कोई चाहता है कि उसका वीडियो सबसे अलग और शॉकिंग लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक मिलें. इस खतरनाक स्टंट में लोग कई बार अपनी सुरक्षा तक भूल जाते हैं और बड़े जोखिम उठाने लगते हैं. इस तस्वीर में एक खतरनाक और असामान्य स्टंट किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक रील

यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और खासकर युवाओं को प्रभावित कर रहा है.

वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की जमीन पर लेटी हुई है और उसने अपने पैर को ऊपर उठाकर उस पर मिट्टी का बना हुआ छोटा चूल्हा रखा हुआ है. उस चूल्हे में आग जल रही है और ऊपर तवा रखा है, जिस पर खाना बनाया जा रहा है. ऐसे स्टंट अक्सर सोशल मीडिया पर ध्यान पाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये सुरक्षित नहीं होते. यह एक खतरनाक वीडियो शूट है जिसमें लड़की अपने शरीर का इस्तेमाल 'चूल्हा स्टैंड' की तरह कर रही है, सिर्फ वायरल होने के लिए. आज के समय में लोग मानते हैं कि अगर उनका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा तो उन्हें पहचान, पैसा और फेम मिल सकता है.

छोटे भाई को पुलिस अफसर बनते देख फफक पड़ा फॉरेस्ट गार्ड भाई

वर्दी को सलाम, भाई को दिया बड़ा पैगाम

सोशल मीडिया पर दो भाइयों का एक बेहद भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे. यह वीडियो दिखाता है कि खून के रिश्ते और किसी अपने की कामयाबी इंसान को कितनी गहराई से छू सकती है.वायरल क्लिप में दावा किया जा रहा है कि एक शख्स अपने छोटे भाई को मुंबई पुलिस की वर्दी में देखकर खुद को संभाल नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं. छोटे भाई की सफलता उसे अपनी ही कामयाबी जैसी महसूस होती है. वीडियो को इंस्टाग्राम पर असलम शेख ने शेयर किया है. क्लिप में मुंबई

पुलिस का एक जवान पासिंग आउट परेड के दौरान पूरी वर्दी और सेरेमोनियल प्लूम के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है. उसकी चाल में अनुशासन और चेहरे पर गर्व साफ नजर आता है.

नया ट्रेंड हुआ वायरल

शादियों में 'गोरिल्ला डांस' का क्रेज

आजकल भारतीय शादियों में एक नया और मजेदार ट्रेंड देखने को मिल रहा है. पहले जहां शादियां पारंपरिक तरीके से होती थीं, वहीं अब नई पीढ़ी कुछ अलग और यादगार करने की कोशिश कर रही है. लोग अब सिर्फ रीति-रिवाजों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी शादी में ऐसा कुछ जोड़ना चाहते हैं जो उनके व्यक्तित्व को दिखाए और मेहमानों को भी एंटरटेन करे. इस ट्रेंड की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई मानी जा रही है. एक शादी में गोरिल्ला की ड्रेस पहनकर डांस करते एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने इसे अपनी शादी में अपनाना शुरू कर दिया. अब बारात और रिसेप्शन में अचानक गोरिल्ला

लोग परंपराओं के साथ-साथ मस्ती और नए आइडिया को भी अपनाने लगे हैं. (Photo: Instagram)

कॉस्ट्यूम पहने कलाकार आकर डांस करते हैं, जिससे माहौल और भी मजेदार बन जाता है. कुछ लोगों का कहना है कि इससे शादी का तनाव भी कम होता है और माहौल हल्का-फुल्का रहता है. कई कपल्स इसे अपनी पसंद और स्टाइल का हिस्सा मानते हैं. अब तो इसके लिए खास ग्रुप और कलाकार भी मिलते हैं, जो शादियों में परफॉर्म करने के लिए बुक किए जाते हैं. एक परफॉर्मेंस का खर्च करीब 8,000 रुपये तक होता है. कुल मिलाकर, यह ट्रेंड दिखाता है कि अब शादियों का तरीका बदल रहा है. लोग परंपराओं के साथ-साथ मस्ती और नए आइडिया को भी अपनाने लगे हैं, ताकि उनकी शादी खास और यादगार बन सके.

'तुम्बाड 2' का आगाज़:नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री से बढ़ा एक्साइटमेंट

भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित हॉरर-फैंटेसी फिल्मों में शुमार Tumbbad के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सालों के लंबे इंतज़ार के बाद इसके सीक्वल 'Tumbbad 2' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मुंबई में आयोजित एक भव्य मुहूर्त सेरेमनी के साथ इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ, जिसमें फिल्म जगत की कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। इस खास मौके पर दिग्गज फिल्ममेकर बोनी कपूर भी मौजूद रहे और टीम को शुभकामनाएं दीं।सीक्वल को लेकर सबसे बड़ी चर्चा इसकी स्टारकास्ट को लेकर है। फिल्म में अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो चुकी है, जो एक जटिल और बहुस्तरीय किरदार निभाते नजर आएंगे। नवाजुद्दीन ने खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें ओरिजिनल फिल्म की कहानी और उसका डार्क माहौल बेहद पसंद आया था, और वह इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं।इस फिल्म को Sohum Shah Films और PEN Studios मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि पहली फिल्म का निर्देशन राही अनिल बर्वे ने किया था, जबकि इसे सोहम शाह ने प्रोड्यूस किया था। 2018 में रिलीज़ हुई इस फिल्म को शुरुआती दौर में ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन समय के साथ यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। खासतौर पर 2024 में री-रिलीज़ के बाद फिल्म को जबरदस्त सराहना मिली, भले ही इसे 'देवरा' और 'स्त्री 2' जैसी बड़ी फिल्मों से टक्कर मिली।करीब 14 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 52.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है। 'Tumbbad 2' के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ में फैला एक भव्य सेट तैयार किया गया है, जिसे किसी पुराने शहर की तरह डिजाइन किया गया है, ताकि फिल्म का डरावना और रहस्यमयी माहौल और भी प्रभावशाली बन सके।इस बार निर्देशन की कमान आदेश प्रसाद के हाथों में है, जबकि सोहम शाह अपने बैनर के तहत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म के साथ

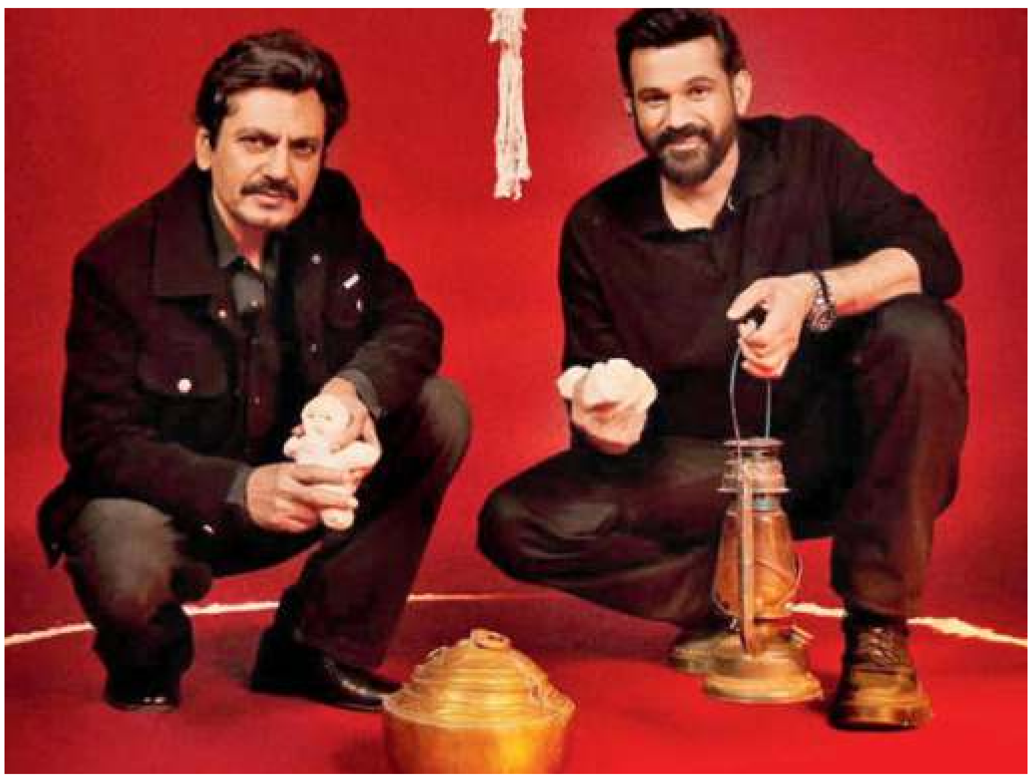

दिग्गज प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गाडा भी जुड़े हैं, जिनकी कंपनी 'RRR' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी बड़ी फिल्मों से जुड़ी रही है। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन 'PEN Marudhar' करेगा।फिल्म के मेकर्स का दावा है कि 'Tumbbad 2' पहले पार्ट से भी ज्यादा रहस्यमयी, डरावनी और विजुअली शानदार होगी। कहानी को और गहराई से विकसित किया गया है, जिससे दर्शकों को एक नया और अनोखा सिनेमाई अनुभव मिलने की उम्मीद है।

अखिलेश-योगी आमने-सामने

यूपी में पोस्टर वॉर से गरमाई सियासत

फिल्म 'धुरंधर-2' के किरदार को अतीक अहमद से जोड़ने पर यूपी की राजनीति गरमा गई है और विपक्ष इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है।लखनऊ समेत कई जिलों में लगे होर्डिंग्स में अखिलेश यादव को फिल्म के विलेन की तरह दिखाया गया है, जबकि योगी सरकार को सख्त कार्रवाई के साथ पेश किया गया है।'यूथ अगेंस्ट माफिया' के नाम से लगे इन पोस्टरों ने चुनावी माहौल में सियासी टकराव और तेज कर दिया है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी की सियासत में फिल्म 'धुरंधर 2' ने बवाल मचा रखा है। माफिया डॉन अतीक अहमद की तरह दिखने वाले किरदार का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन से कनेक्शन दिखाए जाने को लेकर राजनीति गरम है। सपा समेत विपक्षी दल इसे भाजपा का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इस बीच, लखनऊ, अमेठी समेत 10 जिलों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग में एक तरफ अखिलेश को फिल्म 'धुरंधर' के विलेन 'रहमान डकैत' की तरह दिखाया गया है। नीचे लिखा है- अखिलेश का ल्यारी राज। होर्डिंग में दूसरी तरफ कन्या पूजन करते योगी की तस्वीर लगी है। नीचे लिखा है- धुरंधर सीएम। होर्डिंग में पूछा गया है- आपको क्या चाहिए? होर्डिंग 'यूथ अगेंस्ट माफिया' नाम की संस्था ने लगवाए हैं। इसमें अखिलेश की तस्वीर के नीचे उनके शासनकाल के दौरान हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली के दंगों की खबरों की कटिंग लगी है। वहीं, सीएम योगी की तस्वीर के नीचे माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर एक्शन की कटिंग लगाई गई है। होर्डिंग में एक तरफ सपा शासन को दंगे, अराजकता और माफियाराज से जोड़कर दिखाया गया है। लाल टोपी, काला चश्मा लगाए अखिलेश की एडिट की हुई तस्वीर लगी है। इसमें अखिलेश 'रहमान डकैत' की तरह दिखाए गए हैं। उनकी तस्वीर के नीचे 2012 से 2017 के बीच के सपा शासनकाल के अपराधों की घटनाओं का जिक्र किया गया है। 'धुरंधर' में रहमान डकैत की भूमिका बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने निभाई थी। रहमान डकैत पाकिस्तान के कराची में ल्यारी नाम के इलाके का डॉन था। इसके अलावा, सीएम योगी की सरकार में माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है। लखनऊ में होर्डिंग्स मुख्यमंत्री आवास के आसपास प्रमुख चौराहों, हनुमान सेतु, इंदिरा नगर, हजरतगंज, गोमती नगर में लगाए गए हैं। राजधानी से बाहर मलिहाबाद, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, प्रतापगढ़, अमेठी और गोंडा तक होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग पर 'यूथ अगेंस्ट माफिया' के पदाधिकारियों के नाम और तस्वीरें लगी हैं। सीएम आवास के पास लगी होर्डिंग में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष सिंह, महामंत्री अभिनव तिवारी के नाम फोटो सहित लगे हैं। हालांकि, होर्डिंग को लेकर किसी के तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर 'यूथ अगेंस्ट माफिया' को एक नागरिक संस्था बताया गया है। वेबसाइट के मुताबिक, संस्था घटनाओं का रिकॉर्ड रखने, युवाओं को शिक्षित-जागरूक करने, अपराधों का रिकॉर्ड रखने और यूपी के लिए के सुरक्षित भविष्य के लिए समर्थन जुटाने का काम करती है। सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर-2' से जुड़े एक किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वह किरदार है आतिफ अहमद का। कहा जा रहा है कि आतिफ के रूप में प्रयागराज के माफिया रहे अतीक अहमद का ISI कनेक्शन दिखाया गया है। यही वजह है कि सपा ने फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया था।

मध्यांचल निगम मुख्यालय में खुलेगा कंट्रोल रूम

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए नया कंट्रोल रूम खोलने जा रहा है। राजधानी में गोखले मार्ग स्थित निगम मुख्यालय में इसकी स्थापना होगी। इसका फायदा लखनऊ अयोध्या समेत 19 जिलों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। यहां के किसी गांव और शहर में बिजली नहीं आ रही तो उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यहां सिर्फ बिजली आपूर्ति की शिकायतें दर्ज होंगी। अभी बिजली आपूर्ति से लेकर बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक सहारा 1912 हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर से उपभोक्ताओं के संतुष्ट नहीं होने के मामले आते रहते हैं। इसे देखते हुए मध्यांचल निगम ने यह पहल की है। निगम के निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल ने बताया कि कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिशासी अभियंता को बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम को फील्ड में काम करने वाले जेई, एसडीओ, आपूर्ति में आने वाली खामियों व सामग्री की कमी के बारे में भी बता सकेंगे। इससे समस्या का प्रभावी समाधान संभव होगा। मुख्यालय में इस कंट्रोल रूम को खोलने की तैयारी तेजी से चल रही है। कंट्रोल रूम में उपभोक्ताओं को समस्या दर्ज कराने के लिए कई फोन की सुविधा मिलेगी। इस कंट्रोल रूम में उपभोक्ता की शिकायत दर्ज होते ही त्वरित कार्रवाई होगी। हालांकि, कंट्रोल रूम के नंबर हासिल करने की कार्रवाई चल रही है जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। नए कंट्रोल रूम से लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत जिलों के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

डिजिटल अरेस्ट का जाल:ATS अफसर बन ठगों ने बुजुर्ग महिला से ठगे ₹8 लाख बैंककर्मी ने बचाए ₹5 लाख

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

साइबर जालसाजों ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताकर कृष्णानगर सेक्टर-4 निवासी 78 वर्षीय समाज सेविका वीना खुराना को चार दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। फिर उनसे आठ लाख रुपये वसूल लिए। बैंककर्मी की सतर्कता से उनके पांच लाख रुपये बच गए। बैंककर्मी की सलाह पर पीड़िता ने दो ठगों के खिलाफ 31 मार्च को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वीना के मुताबिक चार मार्च की दोपहर 1:40 बजे उनके पास अनजान नंबर से कॉल आई। फोनकर्ता ने बताया कि वह लखनऊ पुलिस हेड क्वार्टर से सब इंस्पेक्टर विवेक चौहान बोल रहा है। उसने पूछा की क्या यह नंबर आप इस्तेमाल कर रही हैं। हां कहने पर उसने उनसे घर के सदस्यों की जानकारी ली और बताया कि 25 मार्च 2025 को आपके आधार कार्ड के जरिये दो सिम खरीदे गए हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने की दी धमकी: ठग ने समाज सेविका से कहा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकी अफजल खान को गिरफ्तार किया है। उसके पास आपके नाम पर दो सिम मिले हैं। ये सिम आईएसआई के लिए आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे थे। आपको मुंबई एटीएस को बयान दर्ज कराने होंगे। ऐसा ने करने पर आप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। यह सुनते ही वीना घबरा गईं। इसके बाद ठग ने कॉल काट दी। वीना ने बताया कि वह कुछ समझ पातीं तभी उनके पास दोबारा अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ गई। इस बार ठग ने खुद को एटीएस अधिकारी प्रवीण सूद बताया। उसने कहा कि पूछताछ होगी। किसी को कुछ बताने पर जेल भेजने की धमकी दी। इस पर वह मान गईं और ठग ने उन्हें चार मार्च से दोपहर दो बजे से लेकर सात मार्च की सुबह तक डिजिटल अरेस्ट रखा। फिर उनकी व परिवार की जान की सुरक्षा का हवाला देते हुए उनसे आरटीजीएस के जरिये आठ लाख वसूल लिए। आठ लाख वसूलने के बाद ठग धमकाते हुए पीड़िता पर पांच लाख रुपये और देने का दबाव डालने लगा। वीना आलमबाग स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में खाते से पांच लाख रुपये निकालने पहुंचीं तो बैंक कर्मी को कुछ संदेह हो गया। कर्मी ने कारण जानने की कोशिश तो वह घबरा गईं। बैंक कर्मी ने उन्हें शांत कराकर दोबारा पूछा तब उन्होंने पूरी घटना बताई। बैंक कर्मी की सलाह पर समाज सेविका ने कृष्णानगर और साइबर क्राइम थाने में शिकायत की। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि पीड़िता ने जिस बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर की है उसका पता लगाया जा रहा है।

बैंकॉक से आए यात्री के बैग में मिला 3 करोड़ का गांजा बरामद

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंटेलीजेंस यूनिट (एआईयू) ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई की। यूनिट ने एक यात्री के पास से करीब 3 करोड़ रुपये का गांजा बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, एयर एशिया की फ्लाइट संख्या एफडी-146 से बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे एक यात्री पर अधिकारियों को संदेह हुआ। रात करीब 11:30 बजे उसे रोका गया। पूछताछ में यात्री ने अपने बैग में प्रतिबंधित हाइड्रोपोनिक गांजा होने की बात स्वीकार की।यात्री के बैगेज की तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 3.190 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच में आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी शमीम के रूप में हुई है। वह गांजा गोंडा ले जा रहा था। वहां से उसे अलग-अलग स्थानों पर तस्करी करनी थी। मादक पदार्थ जब्त कर लिया गया है और आरोपी को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल, सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। वे तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।

दिव्यांगों और छात्रों ने रोड जाम किया लखनऊ में पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांग का एक्टिंग करके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का मामला गरमा गया। गुस्साए दिव्यांगों और अन्य छात्रों ने आज शाम पारा थाना की मोहन रोड पुलिस चौकी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। छात्रों की दारोगा से उनकी तीखी नोकझोंक हुई।छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ छात्राओं ने दिव्यांगों की एक्टिंग करके वीडियो बनाया। वीडियो पर दिव्यांगों के लिए असम्मानजनक बातें लिखीं। उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसा करने वाली छात्राओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।शिकायतकर्ता प्रहलाद सहित अन्य छात्रों ने मोहन रोड चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर की मांग की। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामान्य और दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से समान अवसर प्रदान करना है। कुछ छात्राओं ने इस उद्देश्य के विपरीत आचरण करते हुए दृष्टिबाधित और अस्थिबाधित दिव्यांगों की नकल की। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के रैंप पर रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छात्रों का कहना है कि यह कृत्य न केवल अमानवीय है, बल्कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का भी उल्लंघन है।

सितंबर में लॉन्च होगी नैमिष नगर योजना: सस्ती दरों पर प्लॉट, ग्रीन कॉरिडोर से मिलेगा बेहतर कनेक्शन

आईआईएम रोड और सीतापुर रोड से लगी नैमिष नगर आवासीय योजना को एलडीए सितंबर में लॉन्च करेगा। प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में योजना के दो सेक्टरों में उपलब्ध भूखंडों के आवंटन के लिए पंजीकरण खोले जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस आवासीय योजना में जमीन की कीमत करीब तीन हजार रुपये प्रति वर्गफीट होगी जो एलडीए की अन्य आवासीय योजनाओं की तुलना में काफी कम होगी। योजना 18 गांवों की 1486 हेक्टेयर जमीन पर लाई जा रही है। एलडीए अब तक इनमें से 150 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कर चुका है और 430 हेक्टेयर के बैनामे के लिए किसानों ने सहमति पत्र भी जमा कर दिए हैं। इसी तरह करीब 580 हेक्टेयर जमीन एलडीए को मिल गई है। अब आधी से कुछ ज्यादा जमीन किसानों से सहमति के आधार पर लेनी है। योजना विकसित करने के साथ एलडीए इन गांवों के उन इलाकों में भी विकास कार्य कराएगा, जो आबादी में हैं और जिनकी जमीन को छोड़ा जाएगा। यहां संपर्क मार्ग, जल निकासी, मैदान, बरात घर, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, स्कूल, पार्क व श्मशान आदि के काम कराए जाएंगे। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यहां जमीन खरीदने और विकास कार्य कराने पर आ रहे खर्च का जो आकलन है, उसके अनुसार यहां जमीन की कीमत तीन हजार रुपये वर्गफीट से नीचे ही रहेगी। ऐसे में उन लोगों के लिए अच्छा अवसर रहेगा, जो पुरानी योजनाओं की महंगी जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। एलडीए के संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि योजना से आवागमन को आसान करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी भी हो गई है। विस्तार के बाद ग्रीन कॉरिडोर इस योजना से सीधे जुड़ जाएगा, जिससे लाखों लोगों का आना-जाना आसान हो जाएगा। इसमें तीन किमी बंधा और करीब सात किमी लंबी रोड बनेगी। ग्रीन कॉरिडोर से जुड़ने से नैमिष नगर से किसान पथ तक आनाजाना भी आसान हो जाएगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि नैमिष नगर योजना को सिंतबर में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। पहले दो सेक्टरों में पंजीकरण खोला जाएगा। योजना में किफायती कीमत पर जमीन मिल जाएगी।

सीबीएसई स्कूलों पर सख्ती: फीस, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर डीएम के कड़े निर्देश

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

हाथरस 7 अप्रैल 2026

जनपद में संचालित सीबीएसई बोर्ड के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्य-पुस्तकों के उचित मूल्य निर्धारण एवं अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विद्यालय शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से 60 दिन पूर्व आगामी सत्र में प्रस्तावित शुल्क को अपनी वेबसाइट अथवा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर सार्वजनिक करें, ताकि अभिभावकों को समय से स्पष्ट जानकारी मिल सके। उन्होंने विद्यालयों को पारदर्शिता एवं शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षिक सत्र 2026-27 में विद्यालयों द्वारा नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं 5 प्रतिशत के योग से अधिक शुल्क में वृद्धि न किये जाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रस्तावित फीस समय से पूर्व सार्वजनिक की जाए।विद्यालयों प्रबंधकों को निर्देशित किया कि यूनिफॉर्म में अनावश्यक परिवर्तन न

किया जाए तथा कम से कम पांच वर्ष तक यूनिफॉर्म यथावत रखी जाए, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। पठन-पाठन में एनसीईआरटी पाठ्य-पुस्तकों का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि किसी भी विद्यार्थी को पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म किसी विशेष दुकान से खरीदने हेतु बाध्य न करने तथा विद्यालय परिसर में पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत संचालित स्कूली वाहनों से संबंधित समस्त डाटाबेस (शपथ पत्र) को निगरानी पोर्टल पर दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 के मध्य अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विद्यालय शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित जनपद के सीबीएसई बोर्ड के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित।

ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी हाथरस

स्टेम रेसिंग लिखित परीक्षा में शामिल हुए बच्चे

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

बांगरमऊ। कंपोजिट विद्यालय धन्नापुरवा सकरौली में स्टेम रेसिंग प्रोग्राम के तहत लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए। परीक्षा बांगरमऊ ब्लॉक के 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कराई गई। परीक्षा में प्राथमिक स्तर के कक्षा तीन से पांच तक के बच्चे शामिल हुए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा छह से आठ तक के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। स्टेम रेसिंग परीक्षा में कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे। डायट से पहुंची टीम में शामिल अखिलेश शुक्ला और रचना सिंह ने कंपोजिट विद्यालय धन्नापुरवा सकरौली में निरीक्षण किया। यहां 155 पचपन बच्चों के सापेक्ष 98 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। रचना सिंह ने बताया कि चयनित छात्रों को दो दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा। इसके बाद ये छात्र जिलास्तरीय स्टेम रेसिंग परीक्षा में भाग लेंगे। इसके बाद अखिलेश शुक्ला और रचना सिंह प्राथमिक विद्यालय भिखारीपुर कस्बा पहुंचे। वहां स्कूल चलो अभियान रैली में भी भाग लिया। रैली में शिक्षक शशांक चौहान, गीता यादव और देवेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेश वर्मा, कौशलेंद्र पाल और ठाकुर प्रसाद भी भी शामिल रहे। स्टेम रेसिंग लिखित परीक्षा कक्षा तीन से आठ तक छात्रों के लिए कराई जाती है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों पर केंद्रित है।

1.30 अरब से बनेंगे 5 नए पुल कानपुर-लखनऊ हाईवे को मिलेगा रफ्तार

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

जाम, खराब सड़क और हादसों के कारण बदनामी का दाग झेल रहे कानपुर-लखनऊ हाईवे पर पांच जगह आशा खेड़ा, नवाबगंज, दही तिराहा, चमरौली व त्रिभुवनखेड़ा में 1.30 अरब रुपये की लागत से पुल बनाए जाएंगे। पुल बनाए के लिए मार्च अंतिम में निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिसके बाद पांचों पुल बनाए जाने के लिए निर्माण एजेंसी जीएस एक्सप्रेस को काम का अवॉर्ड हो चुका है। एनएचआइ का दावा है कि ओवरले का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसलिए अप्रैल के अंतिम अथवा मई के पहले सप्ताह में पुलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं यह काम वर्ष 2027 से पहले पूरा हो जाएगा। पुल बन जाने से आने वाले समय में हाईवे से प्रतिदिन गुजरने वाले लगभग 32 हजार वाहनों को सुगम रफ्तार मिलेगी। आसपास के 100 गांवों के छह लाख लोगों को सीधा लाभ होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) लखनऊ क्षेत्र के परियोजना अधिकार नकुल वर्मा ने बताया कि दही तिराहा पर लगभग आधा किमी लंबे पुल को बनाने में 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नवाबगंज में 800 मीटर के पुल के लिए 55 करोड़, आशाखेड़ा में सर्विस रोड व पुल के लिए 20 करोड़, चमरौली व त्रिभुवनखेड़ा में लगभग 400 मीटर लंबे तीन फुट चौड़े ओवरब्रिज के निर्माण पर 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन पुलों के निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अप्रैल 2025 में भेजी गई थी। इसकी स्वीकृति फरवरी में मिली थी।। इसके बाद अब पुल बनाए जाने के लिए एजेंसी तय हो गई है। सभी स्थानों पर पुल बनाए जाने के लिए मिट्टी का भी परीक्षण पूरा किया जा चुका है।

सोमवार की रात मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश साथी सहित गिरफ्तार

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

पुरवा (उन्नाव)। कोतवाली पुलिस ने सोमवार की रात मुठभेड़ में कानपुर निवासी इनामी बदमाश और फिरोजाबाद निवासी साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए इनामी बदमाश ने 25 फरवरी को दंपती से चार लाख की लूट की घटना कबूल की है। सीओ ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर अजगैन कोतवाली से गैंगस्टर में 25 हजार का इनाम घोषित है। उसके पास मिली बाइक भी चोरी की है। सीओ पुरवा अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि सोमवार रात पुरवा-अचलगंज मार्ग पर शारदा नहर पुल के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मौरावां की ओर जा रहे अपाचे बाइक सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागे। पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दाहिने पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल होकर गिर गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ ने बताया कि गोली लगने से घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम इरफान निवासी ताड़ बगिया थाना जाजमऊ कानपुर बताया है। उसका साथी प्रेम सिंह फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना के भायपुर गांव का निवासी है। पुलिस के मुताबिक इरफान ने 25 फरवरी 2026 को पुरवा कोतवाली के भूपतिपुर गांव निवासी किसान महेश कुमार से पुरवा पेट्रोल पंप के पास जेवर और नकदी सहित चार लाख की लूट की घटना स्वीकार की है। घटना के समय महेश, पत्नी बीनू और दो बच्चों के साथ बाइक से मौरावां थाना के लच्छीखेड़ा गांव में रिश्तेदार के यहां मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। दोनों पुरवा-मौरावां मार्ग पर बनिगांव के पास पीछे से आकर बैग लूटकर मौरावां की तरफ भाग गए थे। सीओ ने बताया कि इरफान अजगैन कोतवाली से गैंगस्टर में वांछित है और उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है। इरफान पर उन्नाव के अलावा लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली व अन्य जिलों में चोरी, लूट सहित 21 मुकदमे दर्ज हैं। घटना के समय दोनों किसी लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। प्रेम सिंह के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। बदमाशों के पास दो दिन पहले चकेरी से चोरी की गई बाइक, तमंचा बरामद किया गया है।

गन्दे नाले में पड़ा मिला पत्रकार का शव राहगीरों की लगी भीड़ पुलिस पहुंची मौके पर

जनपद हाथरस आज सादाबाद सहपऊ मार्ग पर नगला ब्राह्मण के पास बहने वाले गंदे नाले में मिला शव गन्दे नाले में लगभग 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में बनी चर्चा का विषयपत्रकार का शव के मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई मौके पर पुलिस पहुँच गयी। फॉरेंसिक टीम व सीओ सादाबाद अमित पाठक भी लोगों से पूछताछ एवं जांच में लगेमृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं।मृतक की शिनाख्त वेद प्रकाश उर्फ सोनू पुत्र राम प्रकाश शर्मा निवासी हाथरस के रूप में हुई है।मृतक द्वारा चार-पांच दिन पहले हाथरस सदर कोतवाली में अपनी जान के खतरे की आशंका को जताते हुए तहरीर भी दी थी

यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षामित्रों का मानदेय दोगुना बस अड्डों और नए विश्वविद्यालय को मंजूरी

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः ₹18,000 और ₹17,000 कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।पीपीपी मॉडल पर बस अड्डों के निर्माण और ग्रेटर नोएडा में नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी हरी झंडी मिली।

टीवी भारतवर्ष,उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। सरकार ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय लगभग दोगुना कर दिया है। यूपी के 52 जनपदों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके अलावा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि समेत अन्य महापुरुषों की मूर्तियों का व्यापक सौंदर्यीकरण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा पर मुहर लगाते हुए योगी कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2017 में ₹10,000 निर्धारित किए गए शिक्षामित्रों के मानदेय को अब बढ़ाकर ₹18,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाकर अब ₹17,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल माह से लागू हो जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश सरकार पर कुल 1475.27 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 2026 के प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में लिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय वर्ष में 11 माह के लिए देय होगा। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों का मानदेय अब तक केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 60:40 अनुपात में प्राप्त होता था। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्रांश के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में बढ़े हुए मानदेय के कारण इन पर आने वाला अतिरिक्त ₹1138.12 करोड़ का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं शेष 13,597 शिक्षामित्र, जिनका भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उनके लिए ₹119.65 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार भी प्रदेश सरकार उठाएगी। संदीप सिंह ने बताया कि इसी प्रकार अंशकालिक अनुदेशकों को भी बड़ी राहत दी गई है। वर्ष 2017 में निर्धारित ₹9,000 मानदेय को बढ़ाकर अब ₹17,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर ₹217.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई माह में दिए जाने वाले भुगतान में यह वृद्धि शामिल होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस क्रम में ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके विनियमन एवं संचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर 'मेट्रो विश्वविद्यालय' स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण के उपरांत स्वीकृति दी गई है।

कानपुर की फूलबाग फल मंडी में आग का तांडव

.टीवी भारतवर्ष कानपुर

यूपी के कानपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है। शहर के व्यस्त फूलबाग इलाके स्थित फल मंडी में सोमवार को दोपहर के समय अचानक लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस दौरान कई सिलेंडर में भी ब्लास्ट की बात सामने आई। आग लगने का कारण पोल से शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र के पास स्थित इस फल मंडी में आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि देखते ही देखते कई दुकानें, गोदाम और थोक स्टोर जलकर राख हो गए। प्राथमिक अनुमान के अनुसार, इस घटना में करोड़ों रुपए का सामान नष्ट हो गया है, जिससे सैकड़ों व्यापारियों की जिंदगी और उनकी गृहस्थी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग मंडी के एक हिस्से में अचानक भड़की और कुछ ही मिनटों में आसपास फैल गई। फल मंडी में फलों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के खोखे, गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक की सामग्री और अन्य ज्वलनशील पदार्थ बड़ी मात्रा में रखे रहते हैं। इन्हीं चीजों के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं की वजह से आसपास की दुकानों तक पहुंच गई। स्थानीय व्यापारियों ने शुरुआती दौर में खुद पानी और अन्य साधनों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटों की तीव्रता के आगे उनकी प्रयास नाकाफी साबित हुए।

गाजियाबाद पुलिस पर खड़े हुए सवाल

टीवी भारतवर्ष,गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक ही गैस एजेंसी से चोर दो बार में 26 भरे सिलेंडर चोरी करके ले गए। पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। जानकारी के मुताबिक चोर गोदाम की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और 14 भरे हुए गैस सिलेंडर ले गए। हैरानी की बात ये है कि कुछ दिन पहले भी इसी एजेंसी से 12 भरे सिलेंडर चोरी हो चुके हैं। मामले में शिकायत पहले भी दर्ज कराई गई थी, दोबारा से भी दर्ज कराई गई है। लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। एजेंसी मैनेजर के मुताबिक, करीब 90 हजार रुपये का नुकसान हो चुका है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मैहर में जमाखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जिले में अवैध डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। इस दौरान करीब 20 हजार लीटर अवैध डीजल और भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किए गए। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने की खबर मिलते ही कई ढाबा संचालक मौके से फरार हो गए। छापेमारी में अमरपाटन क्षेत्र से 14 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा, ढाबों की तलाशी में कुल 47 लीटर अवैध शराब भी मिली है। पुलिस ने बताया कि अब तक 9 मामले दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई अभी जारी रहेगी।

जिलाधिकारी अतुल वत्स ने ओचक निरीक्षण कर कर पटल सहायकों से उनके कार्यों के बारे में जानकारी की

टीवी भारतवर्ष हाथरस

।कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय व जिला पूर्ति कार्यालय का जिलाधिकारी अतुल वत्स ने औचक निरीक्षण कर पटल सहायकों से उनके कार्यों के बारे में जानकारी की तथा उपलब्ध पत्रावलियों का अवलोकन कर आवश्यक अभिलेखों/पत्रावलियों का अद्यतन रूप से रख-रखाव की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों, वितरित की गई धनराशि एवं प्रगति, काशीराम आवास शहरी योजनान्तर्गत निर्मित/आवटिंत भवनो, पी0एम0 स्वनिधि योजना आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी कर कहा कि आवासों के सत्यापन का कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होने पी0एम0 स्वनिधि योजना के लाभार्थियो को नियमित रूप से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिससे कि वह अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इस मौके पर उन्होने उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण कर समस्त कर्मचारियों को कार्यालय में ससमय उपस्थित रहकर कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक सम्पादित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला समन्वयक पी0एम0ए0वाई0 को 2.0 योजना में लम्बित आवेदनो पर समन्वय विस्थपित करते हुये अविलम्ब आवेदनो का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात् उन्होंने जिला पूर्ति कार्यालय/स्टोर रुम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण कर तैनात कर्मचारियों के कार्य विभाजन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लिये गये अर्जित/आकस्मिक अवकाशों के बारे में भी जानकारी की। स्टोर रुम के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनावश्यक सामग्री रखी हुई है, जिस पर जिलाधिकारी ने निस्प्रोज्य/अनावश्यक सामग्री का निस्तारण कराने तथा साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने तथा आवश्यक अभिलेखों/पत्रावलियों का अद्यतन रूप से रख-रखाव की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनसमस्याओं के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिये शासन की प्राथमिकता व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वह अपने कार्यालयों में समय से उपस्थित रहकर लोगों की समस्या-शिकायतों की सुनवाई करके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, पटल सहायक आदि उपस्थित रहे।